Statement

(a) The production of jute textiles/bages for the last three years is given below:

(Qty: In tonnes)

Year (July-June)	Total production of Jute textile/bags	Of which production of sacking bags and		Demand from end-user sectors on the basis of actual off-take			Phosphatic fertilisers
		tarpaulin used for packaging purposes expensively	cloth Food grains	Sugar	Cement	Urea	
1990-91	1421.8	918.9	435.8	174.9	97.5	120.0	Not Packed in jute bags
1991-92	1271.0	731.3	320.3	179.8	65.0	108.5	
1992-93	1342.8	807.0	429.9	156.6	23.5	101.6	

Note: Out of total production of foodgrains, studies indicate that about 40% are available as marketable surplus half of which is packed in second-hand bags and half in new bags. This means only 20% of foodgrains production is packed in new jute bags.

(b) Final estimates of raw jute production as released by Agriculture Ministry during last three years are indicated below:

(In '000 tonnes).

Year (July-June)	Production (In 2'000 bales, of 180 Kgs.)	Equivalent Tonnage quantity
1990-91	91,03	16,39
1991-92	101,82	18,33
1992-93	89,88	16,18

Import of Raw Jute

169. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that raw jute had to be imported to meet the requirements of jute packaging materials;

(b) if so, the foreign exchange outgo for such imports during the last three years;

(c) whether it is a fact that indigenously available HDPE woven sacks and bags could be alternated for jute bags, resulting in not only saving of country's foreign exchange but also provide a boost to the development of small and medium scale HDPE woven sacks industry;

(d) if so, what is the relevance of Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 restricting the use of HDPE woven sacks bags in packing of materials like foodgrains, cement, fertilisers, sugar etc; and

(e) whether there is any proposal before Government to rescind the aforesaid Packing Act, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Raw jute was not required to be imported in recent past to meet requirement of jute packaging materials as domestic production was more than adequate.

(c) No, Sir. Indigenously available HDPE woven sacks and bags are less suitable for packaging of agricultural produce. There are many advantages of using jute bags as they are made from eco-friendly agro-based raw material without any dependence on import. Use of HDPE woven sacks does not result in any saving of country's foreign exchange but on the contrary leads to outgo of foreign exchange because of

sizeable import content of raw materials which go into manufacture of such bags. Although a large number of small and medium scale plants are engaged in manufacture of HDPE woven sack, majority of the production is, however, controlled by large scale industry.

(d) and (e) The relevance of Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 arises from the need to ensure a fair share of market to both jute and HDPE woven sectors so that both can co-exist in harmonious manner and because of this reason Government does not propose to rescind the Act.

सांसदों द्वारा मंत्रालय से किया गया पत्राचार

170. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1993 तक की अवधि में सांसदों द्वारा वस्त्र मंत्रालय को कितने पत्र लिखे गये और उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पत्रों में से कितने पत्रों की प्राप्ति-रसीद भेजी गई;

(ग) कितने पत्रों के मामले में अन्तिम (फाइनल) उत्तर भेजे गये; और

(घ) मंत्रालय द्वारा क्रमशः 'हां' अथवा 'नहीं' में दिये गये अन्तिम (फाइनल) उत्तरों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के एककों का आधुनिकीकरण

171. **श्री अहमद मोहम्मदभाई पटेल:**
श्री सुरेश पचौरी:
श्री सोम पाल:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने 56 से अधिक एककों के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए 5-सूत्रीय योजना अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें कौन-कौन सी हैं;

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अपनी मिलों के साथ-साथ निगम द्वारा अधिगृहीत मिलों का आधुनिकीकरण किए जाने से उनके किस सीमा तक व्यवहार्य होने की सम्भावना है;

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की आधुनिकीकरण योजना को किस सीमा तक पुनरुज्जीवित किया जाएगा;

(ङ) 5 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी; और

(च) क्या इस योजना में कर्मकारों के हितों को ध्यान में रखा गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) से (च) सूती वस्त्र अनुसंधान संघ ने एन टी सी की 79 मिलों का आधुनिकीकरण करने की एक योजना बनाई है जिस पर 2005.67 करोड़ रु० का व्यय होगा। ऐसी आशा है कि एन टी सी इस योजना के क्रियान्वयन के 2 वर्षों के भीतर अर्थक्षमता प्राप्त कर लेगा। यह योजना एन टी सी के मामलों पर परामर्श करने के लिए विशिष्ट समिति को प्रस्तुत कर दी गई है तथा इसके क्रियान्वयन से पहले इसका रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।